सहमति लेने हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के लिए सम्पर्क स्थापित नहीं किया था । अतः तंग किए जाने की सूचना निराधार है ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अलावा जिसके पास डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक सुविधा नहीं है, एस०आई० टी० ने तकनीकी सहायता के लिए अन्य विशेषज्ञ संगठनों से सम्पर्क किया था ।

Welfare of farmers engaged in sericulture

4099. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have evolved any plan for the welfare of farmers engaged in sericulture in the State of Madhya Pradesh and for purchasing cocoon from them at remunerative prices; and

(b) if so, what are tre details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) The schemes for promotion of sericulture including those specifically meant for welfare of sericulture farmers are basically formulated and implemented by the respective State Governments. However, in order to supplement the efforts of the State Governments, the Central Silk Board provides necessary R&D, Extension, Training & infrastructural support for development of sericulture in various States including Madhya Pradesh. In order to offer remunerative prices to the tribal tasar rearers of Madhya Pradesh, the Central Silk Board has established a Raw Material Bank Sub-Deport at Raigarh. Besides, the Board has also established a Cocoon Market (Mulberry) at Jagadalpur.

पटसन की बोरियों का निर्यात

4100. **श्री विनोद शर्मा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पटसन की बोरियों के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 30,000 टन है और इसमें से 6000 टन पटसन की बोरियों का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है तथा शेष पटसन की बोरियों का देश में ही उपयोग कया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार द्वारा उर्वरकों और सीमेंट की पैकिंग में अन्य सिथटिक सामग्री के प्रयोग की अनुमति दिए जाने के निर्णय से पटसन की बोरियों के घरेलू उपयोग में कमी आ जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पटसन उद्योग के लिए कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा करके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन की बोरियों की बिक्री सुलभ कराने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पटसन बोरों का निर्माण करने के लिए सैकिंग और हैसियन के उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता 90–95 हजार टन प्रति मास होने का अनुमान लगाया गया है तथापि, अप्रैल-जून 1992 के दौरान पटसन बोरों का औसत उत्पादन लगभग 62,000 टन प्रति मास रहा है जिसमें से 50/51000 टन की घरेलू खपत हुई तथा 4000 टन निर्यात किया गया ।

(ख) सरकार ने सीमेंट का 65 प्र०श० से 70 प्र० श० उत्पादन तथा यूरिया के समस्त उत्पादन को पटसन में पैकेजिंग करने के लिए आरक्षण आदेशों में अभी तक संशोधन नहीं किया है ।

(ग) और (घ) सरकार विश्वव्यापी निविदाओं में सहभागिता के घाटों को वह अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेकर, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करके, बाजार अध्ययन करके, आयातकों और अन्त-प्रयोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करके वाणिज्यिक आसूचना तथा प्रचार अभियान चला कर व्यापार और उद्योग को सेवा प्रदान करके पटसन बोरों के निर्यात को बढ़ा रही है ।

Export of cloth

4101. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJI RAO SHINDE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the quantity and value of cloth exported during the last three years; and

(b) the unit price per meter of cloth received in these three years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT-: (a) and (b) The quantity, value and the unit price of the cotton cloth exported during the last three years is given below:

Year	Quantity (Million sq Mtrs)	Value (Million Rs.)	Unit Value (Rs./sq Meter)
1989-90	909	9404	10.35
1990-91	1038	11965	11.53
1991-92	1302	17067	13.11

Source: Texprocil, Bombay.

Shifting of Central Muga Research and Training Centre at Kalipani, Assam

4102 SHRI BHADRESHWAR BURAGOHAIN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to shift the Central Muga Research and Training Centre at Kalipani in Jorhat, Upper Assam to out side Assam; and

(b) if so, what are reasons for depriving Assam of the said institute where muga and adi culture is an age old tradition and culture of Assam?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Bringing JCI under Ministry of Agriculture from the Ministry of Textiles

4103. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to transfer Jute Corporation of India from the Ministry of Textiles to the Ministry of Agriculture;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (c) The Ministry of Textiles do not propose *to*